लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2962
उत्तर देने की तारीखः 13.03.2018

वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केन्द्रों हेतु प्रस्ताव

2962. श्री उदय प्रताप सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्ष 2016-17 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से वृद्धाश्रमों और नशामुक्ति केन्द्रों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसकी राज्य-वार विद्यमान स्थिति क्या है; और
(ग) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री विजय साम्पला)

(क) और (ख) जी, हां। सरकार को 2016-17 और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केन्द्रों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वृद्धाश्रमों के प्रस्तावों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है। नशा मुक्ति केन्द्रों के प्रस्तावों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है।

(ग) सहायता अनुदान जारी करने के प्रस्तावों पर, संगत योजनाओं के मानदण्डों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी दृष्टि से प्रस्तावों के पूर्ण होने तथा निधियों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन कार्रवाई की जाती है। निधियां जारी किया जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अतः सहायता अनुदान जारी किए जाने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

अनुबंध-I

दिनांक 13.03.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2962 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना के तहत वृद्धाश्रमों के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2016-17 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			2017-18 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्थिति		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्थिति	
			जारी अनुदान	लंबित मामले *		जारी अनुदान	लंबित मामले *
1	आंध्र प्रदेश	51	42	9	42	31	11
2	बिहार	2	2	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	1	0	1	1	1	0
4	गोवा	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	7	1	6	6	1	5
6	हरियाणा	6	3	3	4	3	1
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	38	30	8	12	0	12
11	केरल	3	4	-1	5	3	2
12	मध्य प्रदेश	7	4	3	37	3	34
13	महाराष्ट्र	26	15	11	38	12	26
14	ओडिशा	43	27	16	56	17	39
15	पंजाब	3	0	3	0	0	0
16	राजस्थान	1	1	0	2	2	0
17	तमिलनाडु	53	48	5	50	43	7
18	तेलंगाना	15	9	6	13	5	8
19	उत्तर प्रदेश	13	10	3	8	5	3
20	उत्तराखंड	5	5	0	0	0	0
21	पश्चिम बंगाल	16	11	5	2	1	1
22	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
23	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
24	पुडुचेरी	0	0	0	3	0	3
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
26	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
27	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
28	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
30	असम	10	10	0	0	0	0
31	मणिपुर	20	14	6	0	0	0
32	मेघालय	0	0	0	0	0	0
33	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
34	नागालैंड	2	1	1	1	0	1
35	त्रिपुरा	3	2	1	2	0	2
36	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
कुल		**325**	**239**	**86**	**282**	**127**	**155**

* विभिन्न कारणों से लंबित मामलों में सहायता अनुदान जारी नहीं किया जा सका जिनमें गैर-सरकारी संगठनों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होना/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों से लंबित स्पष्टीकरण/कालातीत मामले अथवा छानबीन समिति द्वारा गैर-संस्तुति अथवा विचारार्थ लंबित मामले इत्यादि शामिल हैं।

अनुबंध-II

दिनांक 13.03.2018 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2962 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण हेतु सहायता की योजना के तहत नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2016-17 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			2017-18 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्थिति		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्थिति	
			जारी अनुदान	लंबित मामले *		जारी अनुदान	लंबित मामले *
1	आंध्र प्रदेश	8	8	0	12	3	9
2	बिहार	18	16	2	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	4	0	4
4	गोवा	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	31	6	25	15	0	15
6	हरियाणा	11	7	4	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	6	1	5	3	0	3
8	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	1	0	1
9	झारखंड	1	0	1	0	0	0
10	कर्नाटक	28	6	22	15	0	15
11	केरल	23	17	6	22	0	22
12	मध्य प्रदेश	23	14	9	35	5	30
13	महाराष्ट्र	76	50	26	70	7	63
14	ओडिशा	46	31	15	33	2	31
15	पंजाब	24	8	16	1	0	1
16	राजस्थान	20	14	6	7	3	4
17	तमिलनाडु	26	20	6	26	1	25
18	तेलंगाना	10	8	2	6	0	6
19	उत्तर प्रदेश	29	26	3	19	10	9
20	उत्तराखंड	6	3	3	0	0	0
21	पश्चिम बंगाल	12	8	4	2	0	2
22	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
23	दिल्ली	11	6	5	5	0	5
24	पुडुचेरी	3	1	2	2	0	2
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
26	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
27	दमन और दीव	2	0	2	0	0	0
28	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
30	असम	38	13	25	0	0	0
31	मणिपुर	24	19	5	22	0	22
32	मेघालय	2	0	2	0	0	0
33	मिजोरम	12	10	2	10	0	10
34	नागालैंड	7	4	3	8	0	8
35	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
36	सिक्किम	3	0	3	0	0	0
	कुल	**501**	**297**	**204**	**318**	**31**	**287**

* विभिन्न कारणों से लंबित मामलों में सहायता अनुदान जारी नहीं किया जा सका जिनमें गैर-सरकारी संगठनों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होना/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों से लंबित स्पष्टीकरण/कालातीत मामले अथवा छानबीन समिति द्वारा गैर-संस्तुति अथवा विचारार्थ लंबित मामले इत्यादि शामिल हैं।